देश में शिक्षा की स्थिति

साभार: फाइनेंसियल एक्सप्रेस
(05 अक्टूबर, 2017)

बिबेक देबरॉय
(अर्थशास्त्री)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शिक्षा, शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

हमें बार-बार यही बताया जाता है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं या जो कुछ भी हमे पढ़ाया जाता है, उस पर आँख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। अंकमाली (अंगमाली) से 89 किलोमीटर की दूरी पर एक रेस्तरां को 18,000-20,000 रुपये की मासिक वेतन पर पूर्णकालिक पोरोटा निर्माता की आवश्यकता होती है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि त्रिशूर से 60 किलोमीटर की एक पूर्णकालिक सिविल इंजीनियरिंग बी.टेक या डिप्लोमा धारक की आवश्यकता होती है, जिसे मासिक वेतन के रूप में 6000-7000 रुपये दिए जाने की बात कही गयी है। ये केरल के दो अलग-अलग विज्ञापन हैं और निश्चित रूप से यह उचित उदाहरण नहीं पेश करते हैं। हालांकि, कुछ नमूना सर्वेक्षण डेटा नेट पर भी उपलब्ध हैं, भले ही वह आकार में छोटे हो। उदाहरण के लिए, दिल्ली में एक कुक (एक पूर्ण विकसित शेफ नहीं) के लिए 12,000 रुपये प्रति माह और एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा (डिग्री धारक नहीं) के लिए 10,000 रुपये से 12,000 रुपये प्रति माह का वेतन तय किया गया है। एक ड्राइवर के लिए कम से कम प्रति माह 14,000 रुपये का वेतन तय है। इसलिए, शिक्षा और वेतन के बीच के संबंधों में हम प्राथमिकता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेखक ने अपने एक सहकर्मी का उदाहरण देते हुए बताया है कि उनकी नौकरानी / कुक का उम्र 45 के आसपास है और उनके दो बेटे भी है, जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष हैं। इन दोनों ने बारवीं के बाद स्कूल छोड़ दिया और घर पर बैठकर, अपनी मां के वेतन पर गुजारा करने लगे। जब लेखक के सहयोगी ने उन लड़कों से पूछा, आप एक कुक के रूप में काम क्यों नहीं करते? प्रतिक्रिया थी, यह काम लड़कियों के लिए है।

अर्थशास्त्री के बारे में कई चुटकुले किये जाते रहे हैं और इसे केनेथ ऐरो की जगह कई अर्थशास्त्री के रूप में देखा गया है। एकमात्र प्रामाणिक स्रोत कर्ट मोनाश के लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने हार्वर्ड में अध्ययन किया था। लेकह्क ने अपने अनुभव का जिक्र किया है कि वे हार्वर्ड में विलियम जेम्स हॉल के भूतल पर केन एरो के साथ खड़े थे। तीन लिफ्ट हमारे पास से गुजर गये। मैंने मूर्खता से कहा, मुझे आश्चर्य है कि यहाँ हर कोई ऊपर की ओर बढ़ना चाहता है। उन्होंने लगभग तुरंत जवाब दिया: श्आप मांग के साथ आपूर्ति में भ्रमित हैं। श्रम बाजार खंड क्षेत्रीय और भौगोलिक रूप से विभाजित है। हालांकि, क्षेत्र और भूगोल की परवाह किए बिना, अर्थशास्त्र, आपूर्ति और मांग के सिद्धांत, आवेदन करते हैं। थॉमस कार्लाइल का एक उद्धरण एक तोते को शब्द 'आपूर्ति और मांग' सिखाओ, फिर आपके पास एक अर्थशास्त्री होगा। इस अर्थ में थॉमस कार्लाइल को गलत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है।

हमने जो देखा है वह बाजार का समाशोधन मजदूरी है। इस आधार पर, यहाँ यह बता पाना असंभव है कि आपूर्ति या मांग पूरी तरह से है या नहीं, क्योंकि परिणाम दोनों के संयोजन के रूप में होता है। बेरोजगारी पर एनएसएस (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) डेटा दिनांकित हैं, बहुत से लोग बीएसई-सीएमआईई डेटा का उपयोग करते हैं, जो काफी अच्छे सैम्पल के साथ होते हैं। यह घरेलू सर्वेक्षणों पर आधारित होता है, जो कि उद्यम सर्वेक्षणों की तुलना में भारत जैसे देश में बेहतर संकेतक है। बेरोजगारी की दर पर जो दिखाया गया है उस पर मीडिया में चर्चा हुई है। उदाहरण के लिए, सितंबर 2017 में, गोवा और हरियाणा में शहरी बेरोजगारी की दर बहुत अधिक थी (15% से अधिक) हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण बेरोजगारी की दर बहुत अधिक थी (10% से अधिक) और 3 अक्टूबर को अखिल भारतीय दर शहरी के लिए 5.83% और ग्रामीणों के लिए 3.75% थी। जबकि बेरोजगारी दर और इसकी प्रवृत्ति चर्चा के अनुरूप है, जैसा कि सृजन नौकरियों का सवाल है, बेरोजगारी दर की परिभाषा क्या है? इससे पहले, सर्वेक्षण में चार श्रेणियां थी, अर्थात वर्तमान में कार्यरत, कार्यरत नहीं, काम करने के लिए तैयार है और सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश में है। इसलिए या तो कार्य नहीं करने वाले काम करने के लिए तैयार है, लेकिन सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश में नहीं है, या कार्य नहीं करने वाले काम करने को तैयार नहीं है और नौकरी की तलाश में भी नहीं है। बेरोजगारी की दर को नियोजित नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में गणना की जाती है, लेकिन काम करने के लिए तैयार है और सक्रिय रूप से कुल श्रम शक्ति के एक प्रतिशत के रूप में नौकरी की तलाश में है, जहां कुल श्रम बल उन सभी लोगों का योग है जो कार्यरत हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे नौकरी की तलाश कर रहे हैं।

हमें बेरोजगारी दर पर निश्चित रूप से चर्चा करनी चाहिए। हालांकि, लेखक के द्वारा उदाहरण के साथ शुरू किया गया मामला, एक ऐसा पहलू है जो प्रथागत चर्चा से गायब है। यह भारत में बेरोजगारी के एक दस्तावेज में हाइलाइट किया गया है, जो एक ही सर्वेक्षण से उत्पन्न सांख्यिकीय प्रोफाइल है। यह मानक बेरोजगारी की दर है, लेकिन इसमें बेरोजगार और काम करने के इच्छुक लोग भी शामिल है, जो कि नौकरियों की खोज में निष्क्रिय है। दोनों दरों के बीच का अंतर 15-19 आयु समूह में सबसे अधिक है, उसके बाद पुरुषों के लिए 20-24 आयु समूह है, जबकि यह महिलाओं के लिए सभी आयु वर्गों में समान है। श्रम और उनके प्रतिच्छेदन के लिए घटती वस्तुओं की आपूर्ति और मांग की जा रही है, बाकी सब कुछ एक ही है, मजदूरी घटता या बढ़ता है जब आपूर्ति या मांग घटता या बढ़ता है। लेखक के अनुसार, शिक्षा और कौशल के बीच कोई संबंध है या इसमें कोई कमी है। कुछ शैक्षिक प्राप्ति कौशल के अधिग्रहण में मदद कर सकता है, लेकिन सहसंबंध मजबूत नहीं है। महिलाओं के लिए, अंतर उम्र भर एक समान है। हालांकि, युवा पुरुषों के लिए, नौकरी चाहने वालों की धारणा समर्थित होने की तुलना में एक मजबूत सहसंबंध की हो सकती है।

संबंधित तथ्य

समस्या

- मुख्य समस्या शासन की गुणवत्ता (Abysmal Quality of Governance) में कमी मानी गई है।
- शिक्षा प्रणाली 'समावेशी' नहीं है।
- शिक्षक प्रबंधन, शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन के स्तर पर कमी।
- पाठ्यक्रमों में व्यावहारिकता की कमी।
- स्कूल स्तर के आँकड़ों की अविश्वसनीयता।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिये किये गए प्रावधानों को लागू न किया जाना।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) को जमीनी स्तर पर लागू न किया जाना इत्यादि।
- अवसंरचना का अभाव।
- शिक्षा संस्थानों की खराब वैश्विक रैंकिंग।
- प्रदान की गई शिक्षा और उद्योग के लिये आवश्यक शिक्षा के बीच अंतर।
- महंगी उच्च शिक्षा।
- लैंगिक मुद्दे।
- भारतीय बच्चों के लिये आधारभूत सुविधाओं की कमी।

समाधान

- शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- सरकारी खर्च को बढ़ाना।
- समावेशी शिक्षा प्रणाली पर जोर देना।
- गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- शिक्षा क्षेत्र में ढाँचागत विकास हेतु 'पीपीपी मॉडल' को अपनाना।
- समावेशी शिक्षा नीति का निर्माण करना।

सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम

- सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु 'टी.आर. सुब्रह्मण्यम समिति' का गठन किया गया था। समिति ने शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नया सिविल सर्विस कैडर बनाने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) का उन्मूलन, कक्षा-V तक निरोधक नीति (no-detention policy) जारी रखना और प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा देने जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे। इस समिति के प्रावधानों को सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है।
- सरकार ने हाल ही में भारतीय शिक्षा नीति को तैयार करने के लिये 'के. कस्तूरीरंगन समिति' (K. Kasturirangan) का गठन किया। इस समिति का प्रमुख कार्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समकालीन बनाने, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश जैसे कई महत्त्वपूर्ण प्रावधानों पर रोडमैप तैयार करना है।

नो डिटेंशन पॉलिसी शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) का अहम् हिस्सा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। शिक्षा की धारा 21ए के तहत 6 और 14 वर्ष की उम्र के बीच प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया गया है और प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं। इस अधिनियम में सभी निजी स्कूलों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) के गरीबों और अन्य श्रेणियों के बच्चों के लिए 25% सीटें (सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजना के हिस्से के रूप में राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए) आरक्षित करना आवश्यक हैं।

धारा-16 के तहत अधिनियम, पढ़ने, लिखने और कक्षा को पास करने में असमर्थ होने के कारण विद्यालय छोड़ने वालों की उच्च दर के संबंध में, स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और शिक्षित नागरिकता रखने के लिए कक्षा आठवीं तक किसी छात्र को विद्यालय आने से रोकना या विद्यालय से निष्काषित करने से रोकता है।

- न्यूयॉर्क के 'पी.ई.यू. रिसर्च सेंटर' (Pew Research Center) द्वारा विश्व के 90 से अधिक देशों में स्कूली शिक्षा मानकों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन 'विश्व में धर्म एवं शिक्षा' नाम से किया गया। यह दुनिया के प्रमुख धर्मों के बीच 'शैक्षिक प्राप्ति' पर केंद्रित है। इसमें हिंदुओं में 'शैक्षिक प्राप्ति' का स्तर सबसे कम पाया गया और भारतीय विद्यालयी शैक्षणिक व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया। दूसरी तरफ औसत स्कूली वर्ष के संदर्भ में देखा जाए तो ईसाई धर्म में 9.3 वर्ष, बौद्ध धर्म में 7.9 वर्ष है, जबकि मुस्लिम एवं हिंदू धर्म में औसत स्कूली वर्ष 5.6 वर्ष है, जोकि वैश्विक औसत 7.7 वर्ष से काफी कम है।
- इसी प्रकार का अध्ययन हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कोरिया विश्वविद्यालय के आर.जे. बैरो द्वारा वर्ष 2011 में किया गया था और उसनें भी लगभग इसी प्रकार का निष्कर्ष निकला था।

संभावित प्रश्न

''भारत सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कई उपायों और नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी नीति इस क्षेत्र में व्याप्त कमियों को दूर करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो सकी है।'' इस कथन के संदर्भ में सरकारी नीतियों की असफलता के कारणों, देश की शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान कमियों तथा इन कमियों को दूर करने हेतु उचित समाधानों की व्याख्या कीजिये।

Several measures and policies have been implemented to improve the education system by the government of India, but no policy has so far been able to overcome the shortcomings in this area. In the context of the above statement explain the Relevant measures to remove the short comings prevalent in the education system of the country and reasons for the failure of the government policies. **(200 words)**